कपास का उत्पादन

853. **श्री मंजूर इर्शादबेग :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष लम्बे रेशे और छोटे रेशे वाली कपास का उत्पादन कितना - कितना हुआ था और इससे किस सीमा तक जरूरत पूरी हुई;

(ख) छोटे रेशे की कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये है और चालू वर्ष के दौरान उनके क्या नतीजे निकले हैं;

(ग) लम्बे रेशे की कपास के अतिरिक्त उत्पादन का किस तरीके से उपयोग किया गया है और इस किस्म की कपास की कितनी मात्रा का उपयोग नहीं किया जा सका; और

(घ) इस समय बाजार में कितनी मात्रा में कपास उपलब्ध है तथा चालू वर्ष के दौरान कितनी कपास के उत्पादन का अनुमान है और इसका उपयोग किस तरह से किये जाने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) 1984–85 के दौरान लम्बे/अतिरिक्त लम्बे रेशे और छोटे/मध्यम रेशे की कपास का उत्पादन क्रमश : 38.9 लाख गाठें और 45.7 लाख गाठें होने का अनुमान है । यद्यपि लम्बे/अतिरिक्त लम्बे रेशे की कपास का उत्पादन अधिक हुआ, तथापि छोटे/मध्यम रेशे की कुछ किस्मों के उत्पादन में उनकी देशीय मांग की तुलना में मामूली कमी आई ।

(ख) कपास विकास की केन्द्र द्वारा प्रायोजित चालू योजना अर्थात गहन कपास विकास कार्यक्रम के तहत सरकार प्रभाणीकृत बीजों, हवाई छिडकाव के प्रचालन प्रभार, वनस्पति रक्षण उपस्कर और प्रदर्शन पर राजसहायता प्रदान करती है, प्रजनक तथा आधार बीज उपलब्ध कराती है और अपेक्षित स्टाफ मुहैया करती है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यापक तौर पर कपास की छोटे मध्यम रेशे की किस्मों सहित सभी किस्मों का विकास करना शामिल है । यह कार्यक्रम कपास उगाने वाले 9 मुख्य राज्यों अर्थात पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में तथा कपास उगाने वाले छोटे राज्यों उत्तर प्रदेश तथा उडीसा में भी चल रहा है । चालू वर्ष के दौरान अब तक के संकेतों से पता चलता है कि इन उपायों से कपास की फसल को लाभ हुआ हैं और उत्पादन की सम्भावनायें काफी उत्साहवर्धक है ।

(ग) देशीय बाजार में भंडार के दबाव को कम करने के लिए 1984–85 के दौरान लम्बे और अधिक लम्बे रेशे की कपास को 2.95 लाख गांठों को अधिशेष मात्रा निर्यात के लिए निर्मुक्त की गई ।

(घ) चालू वर्ष के लिए कपास उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी राज्यों से प्राप्त नहीं हुए हैं । तथापि, कपास की अच्छी सम्भाव्यता को देखते हुए, सरकार ने निर्यात के लिए अब तक लम्बे और अधिक लम्बे रेशे की कपास की 10 लाख गांठें, बंगाल देशी की 52,000 गाठें, येलों पिकिन्ज की 25,000 गाठें निर्मुक्त की हैं । सरकार ने इस वर्ष के दौरान दीर्घावधि निर्यात की नीति को उदार बनाने की भी घोषणा की है ।

Drinking Water for Rajasthan Through the Indira Gandhi Canal

584. SHRI B. L. PANWAR: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the ground water in the State of Rajasthan has gone too low and is also not fit for human consumption.;

(b) whether the drinking water will be made available through the Indira Gandhi Canal immediately specially to the western Rajasthan region; and

(c) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI B. SHANKARANAND): (a) The observations made by the Central Ground Water Board indicate that there is neither regional decline in the water levels nor any deterioration in the chemical quality of ground water. However, some decline in water levels in one area of about 700 sq. km. in Jodhpur district has been observed.

(b) and (c) The revised Stage-II Project of the Indira Gandhi Nahar, 1984 provides for supply of 0.65 MAF of water for drinking and industrial purposes in the districts of Churu, Nagaur, Jodhpur, Barmer, Jaisalmer, Bikaner and Sri ganganagar.

Fodder Corporation of India

585. SHRI B. L. PANWAR: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a Fodder Corporation of India so as to save cattle and meet all requirements of the States at the time of famine and droughts; and

(b) if so, by when?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) No, Sir.

(b) In view of (a) above, question does not arise.

Media Advisory Committee

586. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to refer to the reply to Starred question 373 given in the Rajya Sabha on the 13th December, 1985 and state what action Government have taken on the reports of the Joshi Working Group and the G. Parthasarthy Media Advisory Committee ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI V. N. GADGIL) : Report of the Joshi Working Group on software and views of G. Parthasarthy Media Advisory Committee on that are under examination of the Government.

Encroachment on D.D.A. Land in village Todapur, New Delhi

587. SHRI H. HANUMANTHAPPA : will the Ministr of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether D.D.A.'s land has been encroached unauthorisedly in village Todapur, New Delhi and factories and houses constructed on it ;

(b) if so, what is the area of land encroached upon during the last three years ;

(c) what action Government propose to take to remove the encroachment ; and

(d) if the answer to part (c) above be in the negative what are the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH) : (a) A part of the land vested in DDA in the village has been encroached upon and unauthorised residential and commercial structures have been constructed thereon.

(b) The area encroached upon during the last 3 years is 5 Bighas and 10 Bighas.

(c) and (d) A clearance operation for removal of encroachments was undertaken by DDA on 26-3-84. There have, however, been fresh encroachments in the area thereafter. The DDA would be taking action for removal of existing encroachments in accordance with law.